



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 857]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2006/श्रावण 12, 1928

No. 857]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2006/SRAVANA 12, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2006

का.आ. 1257(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री एस० पी० सेल्वासनमुगम, द्वारा राष्ट्रपति को संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन तत्कालीन पांडिचेरी विधानसभा में विधानसभा सदस्य श्री आर० कमलाकनन की अभिकथित निरहता के संबंध में तारीख 25 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने अपनी याचिका में यह प्रकथन किया है कि श्री आर० कमलाकनन को पांडिचेरी एग्री सर्विस एंड इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और अध्यक्ष का उक्त पद संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) के अर्थान्तर्गत लाभ का पद था;

और राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन तारीख 12 अप्रैल, 2006 के एक निर्देश द्वारा इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या तत्कालीन पांडिचेरी विधानसभा में विधान सभा सदस्य श्री आर० कमलाकनन संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन पांडिचेरी विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरहित हो गए थे अथवा नहीं;

और निर्वाचन आयोग को यह निर्देश 17 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हुआ था और कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान श्री आर० कमलाकनन 12 मई, 2006 को विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण पांडिचेरी विधान सभा के सदस्य नहीं रह गए थे;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि श्री आर० कमलाकनन के पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता का प्रश्न इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरर्थक हो गया है कि वह विधान सभा, जिसकी सदस्यता के बारे में श्री कमलाकनन के संबंध में प्रश्न उठाया गया था, पहले ही तारीख 12 मई, 2006 को विघटित हो गई है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री एस० पी० सेल्वासनमुगम की उक्त याचिका, जहां तक वह श्री आर० कमलाकनन के संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी विधानसभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित है, 12 मई, 2006 को पांडिचेरी विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण निरर्थक हो गयी है।

31 जुलाई, 2006

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच-11026(15)/2006-लेग. II]

एन. के. नम्पूतिरि, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देश :

संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन पूर्व विधान सभा सदस्य श्री आर. कमलाकनन की अभिकथित निरर्हता

2006 का निर्देश मामला सं. 47

[संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 12 अप्रैल, 2006 का निर्देश है, जिसके द्वारा इस प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या तत्कालीन पांडिचेरी विधान सभा में विधान सभा सदस्य श्री आर. कमलाकनन संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन विधान सभा सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए थे अथवा नहीं।

2. श्री कमलाकनन, विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री एस.पी. सेल्वासनमुगम द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तारीख 25 मार्च, 2006 की याचिका में उठाया गया था। याचिका में यह दलील थी कि श्री आर. कमलाकनन, विधान सभा सदस्य को पांडिचेरी एग्री सर्विस एंड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। याची ने इस आधार पर पांडिचेरी विधान सभा सदस्य बने रहने के लिए श्री आर. कमलाकनन, विधान सभा सदस्य को निरर्हित करने की मांग की थी कि अध्यक्ष का उक्त पद उपरोक्त उल्लिखित धारा 14(1)(क) के अर्थात्तर्गत लाभ का पद था।

3. आयोग को राष्ट्रपति से निर्देश तारीख 17.4.2006 को प्राप्त हुआ था। श्री एस.पी. सेल्वासनमुगम की याचिका के साथ श्री आर. कमलाकनन की पद पर अभिकथित नियुक्ति की तारीख के संबंध में ठीक-ठीक सूचना नहीं लगी थी और न ही उनकी इस दलील का समर्थन करते हुए कि उनके द्वारा धारित पद लाभ का पद था, कोई दस्तावेज लगा हुआ था। अतः याची को आयोग की तारीख 29 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। याची ने तारीख 5 मई, 2006 का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ “पांडिचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994” की एक राजपत्रित प्रति लगी थी।

याची ने यह कथन किया कि 1994 के उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अधीन “द पांडिचेरी एग्री सर्विस एंड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड” के अध्यक्ष/प्रधान/उप-प्रधान/निदेशक के पद या उसके सदस्यों को निरर्हता से छूट प्राप्त थी। याची ने यह कथन किया कि उसे उक्त अधिनियम के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी और उसने यह अनुरोध किया कि कार्यवाहियों को रोक दिया जाए।

4. इसी दौरान, तारीख 12.5.2006 को, अप्रैल-मई, 2006 में हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के आधार पर नई सभा के गठन से पहले, तारीख 12.5.2006 को सभा के विघटन पर श्री आर. कमलाकनन पांडिचेरी विधान सभा के सदस्य नहीं रह गए, जिससे याचिका और प्रतिनिर्देश संबंधित थे।

5. इस घटना को देखते हुए आयोग के विचार के लिए उद्भूत प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि क्या वर्तमान याचिका में श्री आर. कमलाकनन, विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में उठाया गया प्रश्न संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन आयोग द्वारा राय दिए जाने के लिए जीवित है अथवा नहीं।

6. संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देशों के मामलों में आयोग के समक्ष कार्यवाहियां न्यायिककल्प कार्यवाहियां होती हैं। अतः, ऐसे मामलों में आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अंगीकार किए गए सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नीति द्वारा मार्गदर्शित होता है और उनका अनुसरण करता है। एक साधारण सिद्धांत के रूप में न्यायालय पक्षकारों के बीच जीवित विवाद्यकों पर विचार करते हैं और ऐसे विवाद्यक पर विनिश्चय करने के लिए विचार नहीं करते जो विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र होता है या किसी बाद में घटित होने वाली घटना के कारण निरर्थक हो गया है। ऐसे मामलों में

जिनमें निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान, अभ्यर्थी जिसके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, उसकी मृत्यु या संबंधित सदन में स्थान से उसके त्यागपत्र पर या जहां स्वयं सदन ही विघटित कर दिया गया हो, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रहता, उच्चतम न्यायालय ने अपील को निरर्थक अपील के रूप में माना है और उस आधार पर अपील को खारिज कर दिया है। पोडीपीरेड्डी अच्युत देसाई बनाम चिन्म जोगाराव [(1987) सप्लिमेंटरी एससीसी 42] के मामले में जहां सदन निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

“ इस निर्वाचन अपील में उठाए गए प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण हैं। हम अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों में बल भी देख रहे हैं। इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए रूप से निर्वाचन पहले ही हो चुके हैं और इस रूप में अपील निरर्थक हो गई है, यदि हम निर्वाचन अर्जी को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए मत की विधिमान्यता या अन्य प्रारूप में जांच करें तो हम बेकार में ही अपनी शक्ति गवाएंगे। हम, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की विनिश्चय की विधिमान्यता पर या अन्य पहलू पर कोई राय चाहे वह किसी तरह की हो, व्यक्त किए बिना यह निदेश देते हैं कि यह अपील खर्च के बारे में कोई आदेश किए बिना निपटाई गई समझी जाएगी।”

7. पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने लोकनाथ पधान बनाम वीरेन्द्र कुमार साहु (एआईआर 1974 एससी 505) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

“ विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करना निरर्थक होगा और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, अतः न्यायालय को अपील में उद्भूत प्रश्न के गुणागुण पर विचार-विमर्श करने से इंकार कर देना चाहिए। हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी की ओर से दी गई इस प्राथमिक दलील में काफी बल है। भारत तथा इंग्लैंड में मान्यताप्राप्त और अनुसरित सुस्थापित यह पद्धति है कि न्यायालय को ऐसे विवादक का विनिश्चय करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह विवादक पक्षकारों के बीच में जीवित न हो। यदि कोई विवादक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो और उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो यह लोक समय की बर्बादी ही होगी और न्यायालय के लिए इसका विनिश्चय करने में स्वयं को लगाए रखने में उसके प्राधिकार का उचित प्रयोग भी नहीं है.....

.....प्रस्तुत मामले में, उड़ीसा विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण इस बारे में विचार करना सैद्धान्तिक मात्र हो गया है कि क्या उस तारीख को जब नामांकन फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी नियम 9-क के अधीन निरर्हित था अथवा नहीं। भले ही यह पाया जाए कि वह इस प्रकार निरर्हित था तब भी इससे कोई भी व्यावहारिक परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि उड़ीसा विधान सभा के विघटन के पश्चात् उसके निर्वाचन की अविधिमान्यता निरर्थक और निष्प्रभावी हो गई है.....

.....यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी निरर्हित था, नामांकन की तारीख को विद्यमान तथ्यों पर आधारित था और जहां तक भविष्य की स्थिति का संबंध है, इसकी कोई सुसंगतता नहीं होगी और इसलिए उड़ीसा विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी भी पक्षकार का कोई व्यवहारिक हित नहीं है। न तो इससे अपीलार्थी को लाभ होगा और न किसी व्यवहारिक अर्थ में प्रत्यर्थी पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस बारे में विचार करना पूर्ण रूप से सैद्धान्तिक मात्र होगा कि प्रत्यर्थी नामांकन की तारीख को निरर्हित था अथवा नहीं।”

8. पुनः उच्चतम न्यायालय ने धरतीपकड़ मदन लाल बनाम राजीव गांधी (एआईआर 1987 एससी 1577) में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :

“चुनौती के अधीन निर्वाचन 1981 के निर्वाचन से संबंधित है जिसकी कालावधि लोक सभा के विघटन पर 1984 में समाप्त हो गई, उसके पश्चात् दिसम्बर, 1984 में एक और अन्य साधारण निर्वाचन हुआ था और प्रत्यर्थी लोक सभा के लिए 25वें अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से पुनःनिर्वाचित हो गया था। 1984 के निर्वाचन की विधिमान्यता को दो पृथक निर्वाचन अर्जियों के माध्यम से प्रश्नगत किया गया था और दोनों ही अर्जियां खारिज कर दी गई थीं। प्रत्यर्थी के निर्वाचन की वैधता को अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, एआईआर 1986 एससी 1253 और भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी, (1986) 4 एससीसी 78 : (एआईआर 1986 एससी 1534) में बहाल रखा गया था। चूंकि आक्षेपित निर्वाचन लोक सभा से संबंधित है जो 1984 में विघटित कर दी गई थी, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को वर्तमान कार्यवाहियों में अपास्त नहीं किया जा सकता भले ही निर्वाचन अर्जी विचारण पर अंत में मंजूर कर ली जाए क्योंकि प्रत्यर्थी 1981 में हुए आक्षेपित निर्वाचन के आधार पर लोक सभा का सदस्य नहीं बना हुआ है बल्कि 1984 में उसके पश्चातवर्ती निर्वाचन के आधार पर बना हुआ है। यदि हम अपील को मंजूर करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं तब भी प्रत्यर्थी के निर्वाचन को निर्वाचन अर्जी के विचारण के पश्चात् अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अनुतोष समय बीत जाने के कारण निरर्थक हो गया है। इस दृष्टि से प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अर्जी में उठाए गए आधार सैद्धान्तिक मात्र हो गए हैं। न्यायालय को किसी विवादक का विचार करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि पक्षकारों के बीच वह विवादक जीवित न हो। यदि कोई विवादक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो तो उस दशा में उसका विनिश्चय किसी भी तरह से पक्षकारों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा और यदि न्यायालय ऐसा विनिश्चय करता है तो उससे लोक समय की बर्बादी ही होगी। लार्ड विस्काउंट साइमन ने हाउस ऑफ लार्ड्स में सन लाइफ एस्योरेस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम जर्वीस, 1944 एससी 111 वाले मामले में अपने भाषण में यह मत व्यक्त किया : ‘मैं यह नहीं मानता कि इस हाउस के पास अपीलों की सुनवाई करने के लिए जो प्राधिकार है उसका यह उचित प्रयोग होगा कि यदि वह इस मामले में किसी सैद्धान्तिक मात्र प्रश्न का विनिश्चय करने में अपना समय लगाता है जिसका उत्तर प्रत्यर्थी को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता। इस हाउस द्वारा निपटारा किए जाने के लिए उपयुक्त अपील की एक अनिवार्य गुणवत्ता यह है कि पक्षकारों के बीच उस वास्तविक विवादित विषय पर विचार होना चाहिए जिसपर हाउस जीवित विवादक के रूप में विनिश्चय करने के लिए विचार करता है।’ ये मत इस न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करने में सुसंगत है।”

5403 63/06-2

9. आयोग ने निर्देश मामलों में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का लगातार अनुसरण किया है जहां वह सदस्य जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, आयोग द्वारा राय दिए जाने से पूर्व और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रश्न का विनिश्चय किए जाने से पूर्व, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है। ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा अभिकथित सतत राय यह थी कि निर्देश निरर्थक हो गया था। ऐसे कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए श्री रणजी भाई चौधरी और गुजरात विधान सभा के बारह अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 ईएलआर 354) तारीख 17.06.1971 की आयोग की राय, श्री लजिन्दर सिंह बेदी और पंजाब विधान सभा के दो अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 ईएलआर 360) तारीख 10.1.1972 की राय, श्री अवधेश सिंह और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दस अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 2.7.1980 की राय, डा. जगन्नाथ मिश्र, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 17.10.1990 की राय, श्री महादेव काशी राय पाटिल, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 27.10.1990 की राय, श्रीमती जयंती नटराजन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 12.7.1992 की राय और सुश्री जयललीता, तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 29.8.1997 की आयोग की राय का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है।

10. डा. जगन्नाथ मिश्र का मामला (1989 का निर्देश मामला 2) तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले के समान था। उस मामले में उठाया गया प्रश्न राज्य सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र की इस आधार पर अभिकथित निरर्हता के बारे में था कि वह एल. एन. मिश्र इन्स्टिट्यूट आफ इकोनोमिक डेवलपमेंट एंड सोसियल चेंज, पटना के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद धारण कर रहे थे। उस मामले में तारीख 10-6-1989 की एक याचिका, तारीख 10-7-1989 को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजी गई थी। उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान, डा. मिश्र ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र 16-3-1990 को सदन के सभापति द्वारा स्वीकार किया गया था। आयोग ने तब यह राय दी थी कि डा. मिश्र के त्यागपत्र के अनुसरण में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है। आयोग ने उस मामले में दी गई अपनी राय में यह संप्रेक्षण किया कि :

“तारीख 16-03-1990 को डा. मिश्र के त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं। अतः यह प्रश्न कि क्या वह उस सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, इस समय विचार के लिए नहीं बचा है क्योंकि अब वह पहले से ही उस सभा के सदस्य नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, आयोग की यह राय प्राप्त करने के लिए कि क्या

डा. मिश्र राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है।”

11. 1992 के निर्देश मामला सं. 1 में, जिसमें राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई तारीख 22-6-1992 की याचिका में उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या श्रीमती जयन्ती नटराजन, तत्कालीन राज्य सभा की आसीन सदस्या ने, इस आधार पर निरर्हता उपगत की है कि वह 5-5-1992 से 15-6-1992 तक केंद्रीय सरकार की अपर स्थायी काउन्सिल थी। याचिका 30-6-1992 को आयोग को निर्दिष्ट की गई थी। श्रीमती नटराजन की सदस्यता की अवधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी। आयोग ने निर्देश को निरर्थक माना क्योंकि सदन की उनकी सदस्यता 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और उस आशय की 12-7-1992 को राय दी थी।

12. सुश्री जे. जयललिता से संबंधित निर्देश मामलों में (1993 का निर्देश मामला सं. 1(जी)-6 (जी) और 1994 का 1(जी) [अनुच्छेद 192 (2) के अधीन तमिलनाडु के राज्यपाल से तमिलनाडु विधान सभा से सुश्री जयललिता की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाने वाले निर्देश] वह विधान सभा, जिसकी वह सदस्य थी और सदस्यता, जो मामलों में उठाए गए प्रश्न की विषयवस्तु थी, निर्देश मामलों के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दी गई थी। विधान सभा के विघटन के पश्चात्, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि मामले निरर्थक हो गए हैं। उस मामले में, लोकनाथ प्रधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए, आयोग ने यह संप्रेक्षण किया था :

“ उक्त प्रश्न के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने पर आयोग का यह मत है कि ऐसी कोई राय अब अनावश्यक होगी। इस प्रश्न पर कि क्या सुश्री जयललिता मई 1996 में पहले ही विघटित हो गई तमिलनाडु विधान सभा के पूर्वतर सदन के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं। इस प्रक्रम पर कोई जांच, अब मात्र सैद्धान्तिक हित में ही होगी और निरर्थक प्रयास होगा। उपरोक्त प्रश्न पर की गई किसी उद्घोषणा से न तो उनकी वर्तमान प्रास्थिति पर किसी भी रूप में प्रभाव पड़ेगा, न ही ऐसी उद्घोषणा से इस प्रक्रम पर किसी अर्थपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति होगी। यह एक सुव्यवस्थित न्यायिक परिपाटी है जो भारत में मानी और अनुपालन की जाती है कि यदि कोई विवादक इस रूप में पूर्णतया सैद्धान्तिक है कि किसी भी रूप में उस पर विनिश्चय का पक्षकारों की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह जनता के समय की बर्बादी होगी। वस्तुतः न्यायालयों के लिए ऐसे सैद्धान्तिक विवादकों का विनिश्चय करने में अपने आपको लगाए रखना, प्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा। श्री बोबदे, लोकनाथ प्रधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने में सही थे। उस मामले में, उड़ीसा विधान सभा के सफल अभ्यर्थी के निर्वाचन को इस

आधार पर चुनौती दी गई थी कि उसकी कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ संविदा विद्यमान है और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के अधीन निरर्हित हैं। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया था, किंतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील लंबित थी, उसी समय उड़ीसा विधान सभा विघटित कर दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए अपील को निरर्थक हो जाने के कारण खारिज कर दिया था।”

13. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि ऐसे सभी निर्देश मामलों में, जिनमें वह व्यक्ति, जिससे शिकायत संबंधित है, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है, आयोग ने लगातार इस आशय की राय दी है कि मामला निरर्थक हो गया है और उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा कोई राय केवल सैद्धान्तिक महत्व की ही होगी। वर्तमान मामला उपरोक्त निर्दिष्ट सुश्री जयललिता से संबंधित निर्देश मामला जैसा है।

14. उपर्युक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित, पूर्व में सभी ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संगत, आयोग की यह सुविचारित राय है कि श्री आर. कमलाकनन के पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित वर्तमान निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरर्थक हो गया है कि वह विधान सभा, जिसकी सदस्यता के बारे में श्री कमलाकनन के संबंध में प्रश्न उठाया गया था, पहले ही तारीख 12.5.2006 को विघटित हो गई है। प्रसंगवश श्री कमलाकनन द्वारा अभिकथित रूप से धारित ‘द पांडिचेरी एग्री सर्विस एंड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड’ के अध्यक्ष का पद ऐसा पद है जिसे पांडिचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से निरर्हता से छूट प्राप्त है।

15. तदनुसार, तारीख 12 अप्रैल, 2006 का निर्देश संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि वह निरर्थक हो गया है।

ह./-

(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त

ह./-

(बी. बी. टंडन)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

ह./-

(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24 जून, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2006

S.O. 1257(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition dated the 25th March, 2006 of alleged disqualification of Shri R. Kamalakannan, Member of Legislative Assembly in the then Legislative Assembly of Pondicherry, under clause (a) of sub-section (1) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 has been submitted to the President by Shri S.P. Selvashanmugham;

And whereas the said petitioner has averred in his petition that Shri R. Kamalakannan was appointed as Chairman of Pondicherry Agro Services and Industries Corporation Ltd. and the said post of Chairman was an office of profit within the meaning of clause (a) of sub-section (1) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963;

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought by the President under a reference dated the 12th April, 2006 under sub-section (4) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 on the question as to whether Shri R. Kamalakannan, Member of Legislative Assembly in the then Legislative Assembly of Pondicherry, became subject to disqualification for being a Member of Legislative Assembly of Pondicherry under clause (a) of sub-section (1) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963;

And whereas the reference was received in the Election Commission on the 17th April, 2006 and during the pendency of the proceedings, Shri R. Kamalakannan, ceased to be a Member of the Legislative Assembly of Pondicherry, on 12th May, 2006, on account of dissolution of the Assembly;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that the question of alleged disqualification of Shri R. Kamalakannan for being a Member of Legislative Assembly of the Union Territory of Pondicherry, has become infructuous, in view of the fact that the Legislative Assembly, the Membership of which was the question raised in respect of Shri Kamalakannan, has already been dissolved on the 12th May, 2006;

2403 48706-3

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (1) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963, do hereby decide that the said petition of Shri S.P. Selvashanmugham in so far as it relates to the alleged disqualification of Shri R. Kamalakannan for being a Member of Legislative Assembly of the Union Territory of Pondicherry has become infructuous on account of dissolution of the Legislative Assembly of Pondicherry, on 12th May, 2006.

31st July, 2006

President of India

[F. No. H-11026(15)/2006-Leg. II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Annex

Election Commission of India

In re:

Alleged disqualification of Shri R. Kamalakannan, former MLA, under section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963

Reference Case No. 47 of 2006

[Reference from the President under Section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963]

OPINION

This is a reference dated 12th April, 2006 from the President of India, under Section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963, seeking opinion of the Election Commission on the question whether Shri R. Kamalakannan, MLA, in the then Legislative Assembly of Pondicherry, had become subject to disqualification for being Member of Legislative Assembly, under section 14(1)(a) of Government of Union Territories Act, 1963.

2. The question of alleged disqualification of Shri R. Kamalakannan, MLA was raised in a petition dated 25th March, 2006 submitted to the President by Shri S.P.Selvashanmugham. The contention in the petition was that Shri R. Kamalakannan, MLA, was appointed as Chairman of the Pondicherry Agro

Service and Industries Corporation Ltd. The petitioner sought disqualification of Shri R. Kamalakannan, MLA for being a member of Legislative Assembly, Pondicherry on the ground that the said post of Chairman was an office of profit within the meaning of the abovementioned Section 14(1(a).

3. The reference from the President was received in the Commission on 17.4.2006. The petition of Shri S.P.Selvashanmugham was not accompanied by precise information about the date of alleged appointment of Shri R. Kamalakannan to the office nor any document supporting his contention that office held by him was an office of profit. The petitioner was, therefore, asked to furnish specific information in that regard vide the Commission's Notice dated 29th April, 2006. The petitioner submitted a letter dated 5th May, 2006, enclosing therewith a gazette copy of "The Pondicherry Members of The Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994".

The petitioner stated that under the provisions of section 3 of the said Act of 1994, the post of Chairman/President/Vice-President/Director or Member of "The Pondicherry Agro Service and Industries Corporation Limited" was exempted from disqualification. The petitioner stated that he was not aware of the said Act and requested that the proceedings be dropped.

4. In the meantime, Shri R. Kamalakannan, ceased to be a Member of the Legislative Assembly of Pondicherry to which the petition and the Reference related, on 12.5.2006, on the dissolution of the Assembly, before constitution of the new Assembly on 12.05.2006, on the basis of the general election to the Legislative Assembly held in April-May, 2006.

5. In view of this development the preliminary issue arising for consideration of the Commission is whether the question of alleged disqualification of Shri R. Kamalakannan, MLA, raised in the present petition, survives for any opinion of the Commission under Section 14(4) of Government of Union Territories Act, 1963.

6. The proceedings before the Commission in cases of references from the President under section 14(4) of Government of Union Territories Act, 1963, are quasi-judicial proceedings. Hence, in such matters, the Commission is guided by and follows the principles, procedures and policy adopted by the Supreme Court and High Courts. As a general principle, the Courts look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event. In cases where during the pendency of an election appeal, the candidate whose election was under challenge ceased to be a member of the House concerned, on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved, the Supreme Court has treated the appeal as infructuous and dismissed the appeal as such. In *Podipireddy Achuta Desai Vs. Chinnam Joga Rao* [(1987) Supp SCC 42], where the House was dissolved during the pendency of the election appeal, the Supreme Court held:

“The questions raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be undertaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any view, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs.”

7. Earlier, the Supreme Court in the case of *Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu* (AIR 1974 SC 505), had held:

“Assembly being dissolved, the setting aside of the election of the respondent would have no meaning or consequence and hence the Court should refuse to embark on a discussion of the merits of the question arising in the appeal. We think there is great force in this preliminary contention urged on behalf the respondent. It is a well settled practice recognised and followed in India as well as England that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it.....

.....In the present case, the Orissa Legislative Assembly being dissolved, it has become academic to consider whether on the date when the nomination was filed, the respondent was disqualified under S. 9-A. Even if it is found that he was so disqualified, it would have no practical consequence, because the invalidation of his election after the dissolution of the Orissa Legislative Assembly would be meaningless and ineffectual.....

.....The finding that the respondent was disqualified would be based on the facts existing at the date of nomination and it would have no relevance so far as the position at a future point of time may be concerned, and therefore, in view of the dissolution of the Orissa Legislative Assembly, it would have no practical interest for either of the parties. Neither would it benefit the appellant nor would it affect the respondent in any practical sense and it would be wholly academic to consider whether the respondent was disqualified on the date of nomination.”

8. Again, the Supreme Court observed in *Dhartipakar Madan Lal Vs Rajiv Gandhi* (AIR 1987 SC 1577) as follows :

“The election under challenge relates to 1981, its term expired in 1984 on the dissolution of the Lok Sabha, thereafter another general election was held in December 1984 and the respondent was again elected from 25th Amethi Constituency to the Lok Sabha. The validity of the election field in 1984 was questioned by means of two separate election petitions and both the petitions have been dismissed. The validity of respondent's election has been upheld in *Azhar Hussain V. Rajiv Gandhi*, AIR 1986 SC 1253 and *Bhagwati Prasad v. Rajiv Gandhi* (1986) 4 SCC 78: (AIR 1986 SC 1534). Since the impugned election relates to the Lok Sabha which was dissolved in 1984 the respondent's election cannot be set aside in the present proceedings even if the election petition is ultimately allowed on trial as the respondent is a continuing member of the Lok Sabha not on the basis of the impugned election held in 1981 but on the basis of his subsequent election in 1984. Even if we allow the appeal and remit the case to the High Court the respondent's election cannot be set aside after trial of the election petition as the relief for setting aside the election has been rendered in fructuous by lapse of time. In this view grounds raised in the petition for setting aside the election of the respondent have been rendered academic. Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time to engage itself in deciding it. Lord Viscount Simon in his speech in the House of Lords in *Sun Life Assurance Company of Canada v. Jervis*, 1944

AC 111 observed; "I do not think that it would be a proper exercise of the Authority which this House possesses to hear appeals if it occupies time in this case in deciding an academic question, the answer to which cannot affect the respondent in any way. It is an essential quality of an appeal fit to be disposed of by this House that there should exist between the parties to a matter in actual controversy which the House undertakes to decide as a living issue." These observations are relevant in exercising the appellate jurisdiction of this Court."

9. The Commission has consistently followed the above judicial principle in the reference cases where the member, against whom complaint was made, ceased to be a member of the House concerned, before opinion was tendered by the Commission and the question decided by the President or the Governor. In all such cases, the consistent view held by the Commission was that the reference had become infructuous. To cite a few such cases, the Commission's Opinion dated 17-06-1971 in the reference case regarding alleged disqualification of Sh. Ranjibhai Choudhary and twelve other members of Gujarat Legislative Assembly (51 ELR 354), Opinion dated 10-1-1972 in the matter of alleged disqualification of Sh. Lajinder Singh Bedi and two other members of Punjab Legislative Assembly (51 ELR 360), Opinion dated 2-7-1980 in the case of alleged disqualification of Sh. Avdhesh Singh and ten other members of Uttar Pradesh Legislative Assembly, Opinion dated 17-10-1990, in the case of alleged disqualification of Dr. Jaganath Mishra, member of Rajya Sabha, Opinion dated 27-10-1990 in the case of alleged disqualification of Sh. Mahadeo Kashiray Patil, member of Rajya Sabha, Opinion dated 12-7-1992 in the case of alleged disqualification of Smt. Jayanthi Natarajan, member of Rajya Sabha, and Opinion dated 29-8-1997, regarding alleged disqualification of Ms. J. Jayalalitha, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, may be seen in this context.

10. The case of Dr. Jaganath Mishra (Reference Case of 2 of 1989), was similar to the present one. The question raised in that case was about alleged disqualification of Dr. Jagannath Mishra, then sitting Member of Rajya Sabha, on

the ground that he was holding the office of Chairman-cum-Director General of the L.N.Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna. In that case, a petition dated 10.6.1989, was referred to the Commission by the President, on 10.7.1989. During the pendency of inquiry by the Commission into the question raised, Dr. Mishra resigned his seat in the Rajya Sabha, and his resignation was accepted by the Chairman of the House on 16.3.1990. The Commission then tendered the opinion that following the resignation of Dr. Mishra, the reference from the President had become infructuous. The Commission in its Opinion tendered in that case, observed :

“ Consequent upon the acceptance of resignation of Dr. Mishra on 16-03-1990, he is no longer a member of the Council of States from that day. Therefore, the question whether he is disqualified for continuing as a member of that Council no longer survives for consideration at present as he is already not a member of that Council now. In these circumstances, the reference received from the President seeking the opinion of the Commission whether Dr. Mishra has become subject to disqualification to continue as member of the Council of States has become infructuous.”

11. In Reference Case No. 1 of 1992 in which the question raised in the petition dated 22.6.1992 submitted before the President, was whether Smt. Jayanthi Natarajan, then sitting Member of Rajya Sabha, had incurred disqualification on the ground that she was an Additional Central Govt. Standing Counsel from 5-5-1992 to 15-6-1992. The petition was referred to the Commission on 30.6.1992. The term of membership of Smt. Natarajan expired on 29-6-1992. The Commission considered the reference as infructuous as her membership of the House had come to an end on 29-6-1992, and tendered opinion to that effect on 12.7.1992.

12. In the Reference Cases relating to Ms. J.Jayalalitha, (Reference Case Nos. 1(G) - 6 (G) of 93 and 1 (G) of 94, [references from the Governor of Tamil Nadu under Article 192 (2)] raising the question of alleged disqualification of Ms.

2403 4826-5

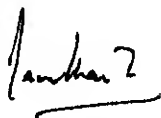
Jayalalitha from membership of Tamil Nadu Legislative Assembly, the Assembly in which she was a member and the membership of which was the subject matter of the question raised in the cases, was dissolved during the pendency of the reference cases. Following the dissolution of the Assembly, the Commission took the view that the cases had become infructuous. In that case, relying on the decision of the Supreme Court in *Loknath Padhan Vs. Birendera Kumar Sahu* (Supra), the Commission observed :

“Having considered all relevant aspects of the said question, the Commission is of the view that any such opinion now would be unnecessary. Any enquiry, at this stage, into the question whether Ms. Jayalalitha had become subject to disqualification for continuing as a member of the earlier House of the Tamil Nadu Legislative Assembly, already dissolved in May, 1996, would be of mere academic interest now, and would be an exercise in futility. Any pronouncement on the above question would not affect her present status, one way or the other, nor would such pronouncement serve any meaningful purpose at this stage. It is a well settled judicial practice, recognised and followed in India, that if an issue is purely academic, in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time, and indeed not proper exercise of authority for the courts to engage themselves in deciding such academic issues. Shri Bobde was right in placing reliance on the decision of the Supreme Court in the case of *Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu* (Supra). In that case, the election of successful candidate to the Orissa Legislative Assembly was challenged on the ground that he had a subsisting contract with the Government of Orissa for the execution of certain works and that he was disqualified under Section 9A of the Representation of the People Act, 1951. The High Court dismissed the election petition, but an appeal was pending before the Supreme Court, when, in the meanwhile, the Orissa Legislative Assembly was dissolved. The Supreme Court dismissed the appeal, as having become infructuous, in view of dissolution of the State Legislative Assembly.”

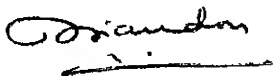
13. It would, thus, be seen that in all reference cases in which the person to whom the complaint pertained ceased to be a member of the House concerned, the Commission has consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous, and any opinion by the Commission on the question raised would only be of academic value. The present case is similar to the Reference case relating to Ms. Jayalalitha, referred to above.

14. Having regard to the above constitutional and legal position, and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past, mentioned above, the Commission is of the considered opinion that the present reference on the question of alleged disqualification of Shri R. Kamalakannan for being a member of the Legislative Assembly of the Union Territory of Pondicherry, has become infructuous, in view of the fact that the Legislative Assembly, the membership of which was the question raised in respect of Shri Kamalakannan, has already been dissolved on 12.5.2006. Incidentally, the office of Chairman of 'The Pondicherry Agro Service and Industries Corporation Ltd.' allegedly held by Shri Kamalakannan is an office specifically exempted from disqualification under Section 3 of the Pondicherry Members of the Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994.

15. Accordingly, the reference dated 12th April, 2006, is hereby returned to the President with the Commission's opinion, under section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963, to the effect that the same has become infructuous.



(Navin B. Chawla)
Election Commissioner



(B.B. Tandon)
Chief Election Commissioner



(N. Gopalaswami)
Election Commissioner

Place : New Delhi

Dated: 24th June, 2006